प्रसंगशः

आलोक मेहता

सपनों की 'स्वर्ण नगरी' का अंधेरा

मुंबई नगरी में सपने बनते-बिखरते और टूटते हैं। फिर भी यह चमचमाती है। लंदन और न्यूयॉर्क में आधी रात के बाद कुछ घंटों के लिए वीरानगी का एहसास हो सकता है लेकिन मुंबई में लगता ही नहीं कि कभी रात वीरानी हो सकती है। रात तीन बजे भी ऑटो रिक्शा का शरीफ ड्राइवर निर्धारित भाड़े पर गैर मराठी मानुस या 20 साल की युवती को भी 20 किलोमीटर दूरी की बस्ती तक पहुंचा देता है। इसी तरह चांद-तारों के साथ बॉलीवुड के कलाकार गर्दिश के दिनों में भी नई सुबह की उम्मीद में खुश रह लेते हैं। यहां हर वर्ग के लोग मेहनतकश दिखते हैं। रीयल प्रोफेशनल अंदाज! ऊंची इमारतों के फ्लैट्स में झाड़ू-पोंछा लगाने और खाना बनाने वाली महिलाएं भी 'पहचान कार्ड' रखकर मशीन की तरह काम निपटाती हैं। सबको अपने काम और जीने लायक आमदनी से मतलब है। हां, राजनीतिक बिरादरी की बात अलग है। उन्हें सत्ता सुख और मेहनत के बिना अधिकाधिक आमदनी से मतलब रहता है। वह मेहनतकश लोगों की भावनाओं और मजबूरियों का पूरा फायदा उठाने में मस्त रहते हैं। तभी तो मुंबई, नासिक, पुणे, नागपुर सहित महाराष्ट्र में राजनीतिक टकराव के बावजूद भारतीय जनता पार्टी, शिव सेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नगर निगमों, नगरपालिकाओं, विधानसभा और विधानपरिषद, लोकसभा-राज्यसभा के चुने हुए अधिकांश प्रतिनिधियों में ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देता। उन्हें जनता की सुविधाओं के बजाय अपनी सुविधाओं, भत्तों, ठेकों से होने वाली अकूत कमाई की अवैध हिस्सेदारी या राजनीतिक प्रश्रय से चल रही आपराधिक वसूली से मतलब रहता है। वृहत्तर मुंबई नगर निगम का इस साल का बजट करीब 26,581 करोड़ रुपए है। पिछले साल 21 हजार करोड़ रुपए था। लेकिन हाई-वे की स्थिति छोड़कर मुंबई शहर की सड़कें पिछड़े हुए उत्तर प्रदेश और बिहार की राजधानियों लखनऊ-पटना से कई गुना बदतर हैं। भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना केंद्र में अपने शासनकाल की सड़क योजनाओं में ठेकों से हुई ऊपरी अवैध कमीशन की कमाई को नहीं स्वीकारतीं लेकिन कई राज्यों में सड़कों का जाल ठीक बिछने पर गौरवान्वित होती हैं। भाजपा तो सड़क योजनाओं का नाम ही 'अटल सड़क योजना' किए जाने और अपने नेता को भारत रत्न देने की मांग कर रही है लेकिन बाल ठाकरे और अटलजी की माला जपने वाले नेता मुंबई की बर्बाद-बदहाल सड़कों के लिए कभी एक आंसू बहाने की कोशिश करते नहीं लगते। मुंबई नगर निगम पानी, सफाई, सड़क, चिकित्सा सुविधाओं के लिए जनता से करोड़ों रुपया वसूल करता है लेकिन असली फायदा नेता वर्ग उठाता है। बरसात के महीनों में तो मुंबई का जलभराव मुसीबत ही बन जाता है। फिर भी नगर निगम या प्रदेश पर राज करने वाली कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 'सक्षम प्रशासक' निकम्मे साबित हो रहे हैं।

राजनीतिक दलों में अच्छी पैठ रखने वाले मुंबई के एक प्रभावशाली बिजनेसमैन ने पिछले साल महाराष्ट्र की चर्चा छिड़ने पर बताया था कि कुछ नेताओं के लिए नोट भरे टैंपो-ट्रक लगभग हर रात पहुंचते हैं। इसकी खेप पहुंचे बिना उन्हें नींद ही नहीं आती। राजनीतिक दल के नेता हों या धर्म के ठेकेदार या कुख्यात अपराधी गिरोह विभिन्न स्तरों पर कमाई में लगे रहते हैं। इसी कारण जगमगाती मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों का हाल बदतर होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक-प्रशासनिक मनमानी के साथ लोगों का आक्रोश अराजकता का रूप ले रहा है। मुंबई-पुणे या नासिक-नागपुर के राजमार्गों की सड़कें अवश्य शानदार दिखती हैं लेकिन उनसे हटकर छोटे कस्बों-गांवों में जाने वाली सड़कों की हालत खस्ता है। इन इलाकों में छोटे-मोटे उद्योग-व्यापार लगाने वालों को नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काए जाने से लोग बाहरी व्यक्ति के धंधे को चौपट करवाने में सहयोग देने लगते हैं। जो फैक्ट्री लगाएगा, उसे देशी-विदेशी खरीदारों को कारखाने दिखाने तथा सामान की ढुलाई का तो अच्छा इंतजाम करना होता है लेकिन जगह-जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यों महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चव्हाण के मुख्यमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश की उम्मीदें बनी थीं लेकिन अजित पवार की वापसी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 'दादागिरी' के सामने पृथ्वीराज की तलवार में जंग ही लग रही है। शरद पवार केंद्र में खाद्यान्न सुरक्षा योजना का विरोध इस आधार पर कर रहे हैं कि किसानों से महंगा अनाज खरीदकर गरीबों को सस्ते दामों पर देना अनुचित है। किसानों के हितैषी होने का दावा करने वाले पवार साहब अपने प्रदेश के खेतीहर किसानों की हालत सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में किसान गरीब हो रहे हैं और उनकी पार्टी के परिजन अमीर हो रहे हैं। पवार साहब को गरीबों को सस्ता अनाज देना खराब लगता है जबकि महाराष्ट्र में उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक निगम पार्षद के पति ने पिछले दिनों 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से सोने की कमीज बनवाकर अपना रुतबा बढ़ाया है। इस 'गोल्ड मेड शर्ट' में साढ़े तीन किलो स्वर्ण लगाया गया। बंगाल के 15 स्वर्णकारों ने दो हफ्ते में यह कमीज तैयार कर दी है। शरद पवार और उनकी पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है। इसी सरकार के वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने नववर्ष के पहले दिन भारतीय जनता को सलाह दी कि देश में अधिक सोना खरीदना बंद करें क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा के भंडार को खतरा पैदा हो रहा है। चिदंबरम और मोंटेक सिंह अहलूवालिया अमीरी-गरीबी के मानदंड तय करते हैं लेकिन अपने सहयोगियों के पार्टीजनों की विलासिता, फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कठोर रुख अपनाने से क्यों बच रहे हैं? मुंबई सिनेमा की तरह वे शायद केवल सपने बेचने में व्यस्त हैं।

चिदंबरम और मोंटेक सिंह अहलूवालिया अमीरी-गरीबी के मानदंड तय करते हैं लेकिन अपने सहयोगियों के पार्टीजनों की विलासिता, फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कठोर रुख अपनाने से क्यों बच रहे हैं? मुंबई सिनेमा की तरह वे शायद केवल सपने बेचने में व्यस्त हैं

alokmehta@nationalduniya.com